>

Title : Further discussion on the motion of thanks on President's Address moved by Dr. (Ms.) Girija Vyas and seconded by Shri P.C.Chacko and the amendments thereto moved on the 5th June, 2009. (Discussion Concluded)

*m01

ओ श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी) : मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए डा0 गिरिजा व्यास के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने जा रहा हूं।

मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी डा0 मनमोहन सिंह, परम आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को बधाई देता हूं जिनकी दूरदर्शिता के कारण 2004 से पांच वर्षों तक राष्ट्र हित एवं लोक हित में जो कार्यक्रम चलाए गए उन पर जनता ने मोहर लगाई, लोगों ने प्रसन्न होकर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया जिसके फलस्वरूप आज पुनः यू.पी.ए. की सरकार बनी। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय एल.के. आडवाणी जी ने भी अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए आदरणीया सोनिया जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तथा आदरणीय नेता सदन प्रणव मुखर्जी को बधाई देते हुए कहा कि पन्द्रहवीं लोक सभा के चुनाव में यू.पी.ए. को जनादेश प्राप्त हुआ है। गत पांच वर्षों में निर्णय लिए गए, योजनाएं बनाई गई, धन की व्यवस्था की गई और उन्हें ईमानदारी से लागू किया गया। गरीब किसानों के पुराने कर्जे माफ कर दिए गए इससे उन्हें भय और आतंक से छुटकारा मिला। भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने का एक सफल प्रयास किया गया। सर्वशिक्षा अभियान और मिड डे मील योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के मामले में एक क्रांति आई। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत बुजुर्ग , विधवाएं और विकलांगों को परिवार और समाज में सम्मान प्राप्त हुआ है। शहरी क्षेत्रों में जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिनुअल मिशन के माध्यम से झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग भी विकास की रोशनी देख सके। सभी वर्ग के लोगों ने सरकार के कार्यों की प्रशंसा की और काम को देखकर वोट दिया और आज एक सशक्त जनादेश लेकर सरकार आई है।

मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री जी को तथा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को जिन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अगले 100 दिन में प्रत्येक वर्ष और पांच वर्ष के लिए क्या प्रतिबद्धताएं होंगा

या कार्यक्रम तथा योजनाएं होंगी , उसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। हर क्षेत्र के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम रखे गए। जनादेश से उत्साहित होकर भारत निर्माण एवं अन्य योजनाओं का जहां लक्ष्य दोगुना कर दिया गया है वहीं पिछले पांच वर्ष के अनुभव के आधार पर उन योजनाओं को और अधिक जनता के लिए लाभकारी बनाया गया है और हर स्तर पर मॉनिटरिंग एवं पारदर्शिता के ऊपर अधिक जोर दिया गया है

---

* Speech was laid on the Table

जहां पिछले कार्यकाल में यू.पी.ए. सरकार ने गरीबों को रोजगार का अधिकार दिया था इस कार्यकाल में खाद्य सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाकर अधिकार दिया जा रहा है जिसमें देहात और शहर के गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को 3 रूपया प्रति किलो की दर से चावल, गेहूं दिया जायेगा, यह बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। राज्य सरकारों के द्वारा अगर भ्रष्टाचार से इस योजना को उनके द्वारा मुक्त कर दिया जाए तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे , कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा। नरेगा और खाद्य सुरक्षा एक साथ ईमानदारी से लागू करने के बाद भूख के कारण जीविका के लिए होने वाले अपराध समाप्त हो जाऐंगे। कोई भी गरीब का शोषण नहीं कर पायेगा। समाज में गैर बराबरी समाप्त होने की तरफ ये एक सशक्त कदम होगा क्योंकि सूची जाति व धर्म पर आधारित नहीं है अतः गरीबी के आधार पर सभी जाति वर्ग के लोग इन योजनाओं में सम्मिलित होते हैं जो वास्तव में समाज में समरसता का संदेश देता है।

लेकिन इसके लिए अनिवार्य है कि राज्य सरकारें वास्तव में गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों का सही ढंग से चयन करें। उत्तर प्रदेश में अन्तिम बार इस प्रकार की सूची वर्ष 2002 में बनी थी, पांच वर्ष बाद इस सूची का रिवीजन होना था , सूचियां सब गलत बनायी गयीं, राज्य में सत्ताधारी दल ने अपने लोगों को जो अमीर लोग थे सूची में डलवा दिया गया। शिकायत होने पर नयी सूची को निरस्त कर दिया गया और आज वर्ष 2002 में बनायी गई सूची से काम चलाया जा सकता है जिसमें उन लोगों के नाम सम्मिलित हैं जिनके पक्के मकान हैं तथा परिवार में कोई न कोई नौकरी कर रहा है। जो वास्तव में गरीब हैं उनके नाम उस सूची में नहीं है। गत वर्ष बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण गरीबों के कच्चे मकान ध्वस्त हो गये और उन लोगों को आर्थिक सहायता इसलिए नहीं मिली क्योंकि उनके नाम गरीबी की रेखा के नीचे वाली सूची में नहीं थे और चैक ऐसे लोगों को मिले जिनके न मकान गिरे थे और गांव में उनके पक्के मकान मौजूद हैं। अगर पुरानी सूची के आधार पर खाद्यान्न वितरित किए गए तो योजना के उद्देश्य की पूरी तरह पूर्ति नहीं हो पायेगी। सभी योजनाओं के लिए बी.पी.एल. सूची को ही आधार माना गया है , चाहे वो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत मुफ्त कनेक्शन देने का हो, इन्दिरा आवास व पेंशन योजना , सभी में इस सूची को आधार माना गया है। गलत सूची बनने से सभी योजनाओं को लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच पायेगा और जिस कल्पना के साथ यह योजना बनाई जा रही है उसके लाभ से गरीब लोग वंचित रह जायेंगे। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से गरीब वर्ग के लोगों के लिए राज्य सरकारों को धनराशि भेजी जाती है। तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी0 चिदम्बरम ने वर्ष 2007 में एन.डी.सी. की बैठक में उल्लेख किया था कि गरीबों के लिए एक रूपए का लाभ पहुंचाने में रूपए 3.65 खर्च होता है और जिस एक रूपए को गरीबों तक पहुंचने की बात कही गयी है उसके बारे में कृपया सुन लीजिए। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में बेबाकी से स्वीकार किया था कि दिल्ली से हम एक रूपया भेजते हैं तो गरीब आदमी तक केवल 15 पैसे पहुंचता है और बुन्देलखंड का व्यापक दौरा करने तथा वहां के लोगों से जमीनी हकीकत जानने के बाद श्री राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में उल्लेख किया कि गरीब के पास केवल 5 पैसे ही वास्तव में पहुंचता है। गरीबों के लिए योजनाएं अच्छी बननी चाहिएं ताकि उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार हो लेकिन डिलीवरी सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो पायेगा।

मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अत्यन्त समीप बाराबंकी से निर्वाचित होकर आया हूं। ये जनपद राजधानी से इतना नजदीक होने के बावजूद अत्यन्त पिछड़ा है और इसका मुख्य कारण यहां के पिछले 25 साल के दौरान इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी सांसद ने इस सदन में कभी भी न तो कोई

प्रश्न पूछ, न ही कोई मामला उठाया । इस लम्बे समय तक उपेक्षित रहे क्षेत्र के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से तथा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से अनुरोध करूंगा । बालिकाओं की शिक्षा हेतु कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है । कई तहसीलों में एक भी डिग्री कालेज नहीं है । मेरा विशेष अनुरोध है कि सर्वशिक्षा अभियान को व्यापक रूप देने की योजना है, उसमें बाराबंकी संसदीय क्षेत्र का विशेष सर्वेक्षण कराकर बालिकाओं के लिए हर ब्लाक स्तर पर एक इंटर कालेज और तहसील स्तर पर एक डिग्री कालेज की व्यवस्था केन्द्रीय योजना के माध्यम से की जाए।

मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि बाराबंकी की रामनगर तहसील घाघरा नदी की बाढ़ से प्रत्येक वर्ष लगभग 5 से 6 लाख की जनसंख्या प्रभावित होती है, आज तक इस समस्या के समाधान हेतु कोई ठोस पहल नहीं की गई । घाघरा नदी पर तटबन्ध बनाये जाने की आवश्यकता है जिसके अनेकों बार प्रस्ताव भी भेजे गए लेकिन केन्द्र सरकार के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई । प्रतिवर्ष लोगों के मकान पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं और बाढ़ के बाद पुनः वे अपने गांव में जाकर झोंपड़ी डालकर अपना व अपने परिवार का सिर ढ़कते हैं । इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत सड़के बना दी जायें जिससे बाढ़ के समय लोग अपने परिवार, बच्चे व जानवरों को लेकर कम से कम उन सड़कों पर अपना बसेरा बना सकें । ये अत्यन्त भीषण समस्या है और इस समस्या का समाधान शीघ्र किए जाने का अनुरोध है । बाराबंकी तथा बहराइच के बीच में घाघरा नदी पर हेमतापुर पर पुल बनाने की बहुत दिनों से मांग की जा रही है जिसे अभी केन्द्र सरकार के द्वारा अनुमोदन किया जाना हे । यदि यह पुल बन जाता है तो बाराबंकी जनपद का क्षेत्र जो नदी के दूसरे पार है वो जनपद से जुड़ तो जायेगा ही उसके साथ बहराइच के लिए सीधा मार्ग बन जायेगा जिससे पेट्रोल, डीजल के रूप में करोड़ों रूपए की प्रतिवर्ष बचत होगी ।

बाराबंकी नगर के समीप विश्व विख्यात देवाशरीफ है जहां पर दुनिया भर के सभी धर्म के लोग वहां पहुंचते हैं । बाराबंकी नगर में लखनऊ-बनारस तथा लखनऊ-गोरखपुर रेलवे फाटक पर घंटों लोगों को इन्जतार करना पड़ता है । बहुत दिनों से ये भी मांग है, इस समस्या के समाधान के लिए एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए जिससे आम जन को सुविधा होगी और देवाशरीफ पहुंचने में कोई असुविधा नहीं आयेगी ।

महिलाओं के लिए आरक्षण की जो केन्द्र सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से प्रतिबद्धता व्यक्त की है उसका मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं । इस विषय पर सदन में विभिन्न प्रकार के विचार प्रकट किए गए आदरणीय शरद यादव जी तथा आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने लोक सभा / विधान सभा में 33 प्रतिशत आरक्षण के वर्तमान स्वरूप पर घोर विरोध प्रकट किया । सभी की बातें सुनने से ऐसा प्रतीत होता है कि वरिष्ठ नेताओं में व्यक्तिगत असुरक्षा की भावना है और कोई सैद्धांतिक विरोध नहीं है । कहा गया है कि बड़े-बड़े नेता सदन में नहीं पहुंच पायेंगे । ऐसा क्यों सोचते हैं हमारे वरिष्ठ नेतागण इतने बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं । बहुत लोग अपनी धर्मपत्नियों के माध्यम से सरकार चलाते रहे हैं । हो सकता है कि उन लोगों को अवश्य कठिनाई होगी जिन्हें ये चयन करना पड़े कि किस पत्नी को वो अपनी जगह राजनीति कराना चाहते हैं । बहुत से बड़े नेता पूरा जोर लगा देते हैं कि अमुक व्यक्ति न चुना जाए मेरे लिए लोक सभा चुनाव में प्रदेश की मुखिया ने मुझे पराजित करने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन जितना विरोध किया उतने ही ज्यादा अन्तर से मैं जीता ।

ये 50औ जनसंख्या को 33औ भी नहीं देना चाहते हैं, जो उचित नहीं है। हमें व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के बारे में सोचना चाहिए । हरेक नेता की अपनी कठिनाई हो सकती है लेकिन उस कठिनाई के कारण राष्ट्र को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा । मेरी प्रबल संस्तुति है कि महिलाओं के लिए आरक्षण जल्दी से जल्दी लागू करने के लिए सरकार अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप अधिनियम लाये ।

किसानों को कर्ज माफी का बहुत लाभ मिला और उन्होंने अपनी कृतज्ञता मतदान के माध्यम से व्यक्त की । बजट भाषण में 31 दिसम्बर,2007 तक बकाया ऋण को कुछ शर्तों के साथ माफ करने की घोषणा की गयी थी । बजट घोषणा के विपरीत आदेश लागू करने में वर्ष 1997 से 2007 तक की अवधि अंकित कर दी गई, जो सही नहीं है । 1997 से पूर्व के बकाया ऋण की धनराशि बहुत कम होगी, लेकिन आज भी गरीब व्यक्ति उस बकाया ऋण का बोझ सहन नहीं कर पा रहा है । मेरा प्रबल अनुरोध है कि वर्ष 1997 के पहले ऋणों पर भी माफी की योजना लागू कर दी जाए ।

मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर डा0 गिरिजा व्यास के द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं ।

SHRI FRANSISCO COSME SARDINHA (SOUTH GOA): Sir, I join my colleagues to support the Motion of Thanks on the Address of the hon. President. The progress made in different fields in the country in the last five years by the UPA Government under the able leadership of UPA Chairperson Shrimati Sonia Gandhi and the hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh and the new policies which are envisaged in the next term have been duly highlighted in the hon. President's Address.

Madam, you can see the country's growth rate, standard of living of people, employment, education and health sectors and for that matter any other field. Our country has done a tremendous progress in the last five years like never before. [R3]

What is to be appreciated is that the people of this country, both young and old, have accepted and approved the performance of the UPA Government. That is the reason why people have given clear mandate to the UPA to go ahead with these developmental policies in the near future.

The world economies are sinking and are in jeopardy under unprecedented recession, but our Indian economy has remained well protected due to the policies adopted by the UPA Government.

The loan waiver scheme to the tune of Rs. 70,000 crore for farmers has not only provided the necessary fillip to the agricultural sector but also put an end to the lamentable suicidal deaths, which we were witnessing for quite a long time in many States. It is very commendable.

Having ushered in the path-breaking Right to Information Act, this Government is empowering the citizens by announcing a

time-bound development programme, which is to be implemented in the first hundred days and not in years. The common man can seek the details of the actual performance achieved under this programme, thereby creating a sense of accountability for those who are entrusted with the responsibility of implementing the programme within the time- frame.

The commitment to enact the Women's Reservation Bill within a time-frame again shows the earnestness and the sincerity of purpose of this UPA Government. Once this becomes a law, it will further transform this society which was the dream of Shri Rajiv Gandhi ji. It was his dream to allow women to have an important role in the transformation of the country.

The Home Ministry's effort to beef up coastal security after 26/11 terror attack should also have special emphasis and focus on Goa as it is one of the most popular tourist destinations on the world tourism map.

The massive expansion in the higher education proposed in the Eleventh Five Year Plan must have a couple of Central Educational Institutions to be also set up in Goa. The discontinuance of the Central Government scheme of giving tax holiday to industries has greatly affected our State of Goa as no new industries are willing to come, and some of the old industries have shifted to other places. This has affected the employment generation in the State. Our State is heavily dependent on tourism industry. As the tourism industry is mostly seasonal, it does not offer employment throughout the year. ...(*Interruptions*)

SHRI RAJIV RANJAN SINGH ALIAS LALAN SINGH (MUNGHYR): Madam Speaker, he can be asked to lay his speech on the Table of the House as he is reading it out. ...(*Interruptions*)

SHRI FRANSISCO COSME SARDINHA : Please do not disturb me. I would like to speak. ...(*Interruptions*) I am not reading the speech. ...(*Interruptions*) It is for Madam Speaker to decide. ...(*Interruptions*)

Madam Speaker, it should not be stopped abruptly. My suggestion was that this scheme which was there for giving tax holiday, which was stopped, should have been done in stages so that these industries which have run away from the State may come back and unemployment problem can be solved.

Regarding the MPLAD Scheme, I would like to say that now we are getting only Rs. 2 crore a year. In my constituency I have around 20 Assembly segments, Rs. 2 crore is not enough. I hope other hon. Members will also agree with me that this has to be increased to Rs. 6 to Rs. 8 crore so that we can do justice to every Assembly segment in the State.[14]

I would also like to bring to the notice of the hon. Minister that in every Central institution, we can recommend two names. Madam, there are five or six Central institutions in each constituency. So, I would again request that every Member should be allowed to recommend at least two students in each institution in that particular constituency. This should be done only for the Lok Sabha Members as the Rajya Sabha Members can recommend anywhere in the State. It is because so many people approach us and we cannot do justice.

Madam, referring to the Golden Quadrilateral, I would request the hon. Minister one thing. We have got three bridges – two small ones in the South i.e. Canacona at Galgibaga and Talporna and the other huge bridge as Zuari which is the artery of Goa. I would request the hon. Minister to look into this so that these bridges are taken up immediately because already the alignment has been fixed. If anything goes wrong with our Zuari bridge**,** South Goa will be cut-off from North Goa.

Madam, with these few words, I appreciate whatever points which have been mentioned in the President's Address. I would request my colleagues and the whole House, to approve this Motion of Thanks.

Madam, I thank you very much for giving me this opportunity.

श्री लालू प्रसाद (सारण): महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। श्री कड़िया मुंडा जी को सदन का उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं क्योंकि कल जब आपका अभिनन्दन समारोह हो रहा था, मैं अनुपस्थित था।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने सरकार द्वारा रचित, लिखित भाषण पढ़कर सुनाया है। मैंने उसे ध्यानपूर्वक सुना है और मोटा-मोटी अध्ययन भी किया है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने सरकार की अगले पांच साल की नीतियों और संकल्पों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़कर हम लोगों का मार्गदर्शन किया है और मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अफसोस नहीं है। जो यूपीए सरकार बनी है, हम वहीं थे और हमने अनकंडिशनल सपोर्ट भी दिया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं उस सरकार के लिए कोई कटु शब्द इस्तेमाल करूं जिसके साथ हम लोग, खास कर मैं व्यक्तिगत रूप से पिछले कई साल से रहे हैं। कई राज्यों में मैं कांग्रेस पार्टी का फ्री-लांसर था और आज हम लोग सरकार में नहीं है, तो वह इनकी वजह से नहीं है। जनता ने हम लोगों को यहां बैठाया है। हम लोग चार आदमी ही सदन में जीतकर आए हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल मास-बेस्ड अनआर्गेनाइज्ड पार्टी है, लेकिन सीपीआई और सीपीएम आर्गेनाइज्ड पार्टीज हैं, बीजेपी के बाद। हम और सीपीआई बराबर में हैं, हम दोनों को चार-चार सीटें मिली हैं और सीपीएम को 16 सीटें मिली हैं।

मैं खासकर माननीय सोनिया जी और उनके सत्ताधारी दल को, जिसमें हमारा भी कंट्रीब्युशन है, को बधाई देता हूं। आडवाणी जी के प्रति, मैं पंडित तो नहीं हूं, लेकिन मैंने कहा था कि उनकी कुंडली में यह नहीं है, वह बात ठीक निकली है। यह दिल्ली नगरी माया की नगरी है। न जाने कितने बाहर वाले आए, राज किया और चले गए।[R5] कितने समाप्त हो गए है और मैं तो यहां निर्गुण की भी बात आजकल सुनता हूं। यह शब्द भी मुझे सुनने को मिलता है। इससे मुझे याद आता है कि - दूल्हा मर गया, दुल्हन मर गई, मर गई बुढ़िया दादी। यहां कोई स्थाई नहीं है, सबको जाना है। कृष्ण चले गए, राम भी चले गए और रहीम भी चले गए। मैंने देखा कि आपके दल में और बाकी के भी दलों में नेताओं के इर्द-गिर्द कुछ न कुछ ऐसे लिमिटेड लोग छाए रहते हैं, वे न जाने नेताओं को कितना ऊपर आसमान तक चढ़ा देते हैं...(व्यवधान) हमें भी चढ़ाया था। ऐसे लोगों के बारे में मैं बोलता हूं कि राजनीति में ये 'टीटीएम' अर्थात ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले लोग।...(व्यवधान) इनकी कोई क्लास नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदया, मुझे अफसोस इस बात का है कि मुलायम सिंह यादव जी और माननीय शरद यादव ने जिस बात की तरफ इशारा किया, उसमें काफी दम है। हम लोग यहां आए हैं, बीजेपी वाले भी बैठे हैं, वे भी बैकवर्ड क्लास के विषय में, दलितों के विषय में अब स्वीकार करने लगे हैं। ज्योति बाबू सरीखे नेता और सीपीआई (एम) का भी क्लास स्ट्रगल में विश्वास है। मंडल कमीशन और सामाजिक न्याय की लड़ाई जब हमने तेज की तो ज्योति बाबू को भी स्वीकार करना पड़ा कि इस देश में जाति भी है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है, हम ऊपर से कितना भी कहें। मुलायम सिंह जी ने जिस बात की चर्चा की, तो मैंने टीवी में एक चैनल पर कांग्रेस पार्टी के एक नेता का बयान सुना कि मुलायम सिंह कहते रहें, हमारे पक्ष में महिला आरक्षण के बारे में पर्याप्त आंकड़ा है। मैं महिला आरक्षण विषय पर आगे चलकर अपने और अपने दल का नजरिया आपके सामने रखूंगा।

महोदया, मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने अपने 100 दिन का कार्यक्रम निर्धारित किया है। मैं भी केन्द्र की सरकार में रहा हूं। माननीय प्रधान मंत्री का स्नेह और प्यार हम सभी को मिला। ऐसे नेक इंसान बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सोनिया जी जैसी भली महिला भी दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है...(व्यवधान) सुनिए, मैं यहां टीटीएम नहीं हूं। जिस आदमी में गुण हैं, उसे बताना चाहिए। टीटीएम तो टीटीएम होते हैं। यह जो पहले 100 दिन का कार्यक्रम बनाया है और स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सम्मान में यह कहा गया है कि अगले पांच साल तक शहरों में जितनी भी झुग्गी-झोंपड़ियां हैं, उन सभी को पक्के मकानों में बदल दिया जाएगा।

दूसरी बात यह भी कही गई है, वादा किया गया है कि 100 दिन कार्यक्रम में प्राथमिकता इस बात पर होगी कि हम बीपीएल के तहत जो परिवार हैं, उन्हें 25 किलो मासिक गेहूं या चावल तीन रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से देंगे। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जो फिगर भारत सरकार के पास है, वह सही नहीं है, चाहे बिहार की हो या अन्य किसी प्रांत की हो। हर प्रांत में बीपीएल का आंकड़ा सही नहीं है। विगत विधान सभा चुनावों में हमने देखा कि कई राज्य सरकारों ने, जिनमें कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की भी हैं, वहां के मुख्य मंत्री और बड़े-बड़े नेता गरीबों को चावल और गेहूं दे रहे थे। यदि केन्द्र सरकार भी गेहूं और चावल बेचना शुरू कर देगी तो मैं समझता हूं कि इस देश के गरीबों को हम क्या दिखाना चाहते हैं। उन्हें अगर आगे बढ़ाना है तो सिर्फ गेहूं, चावल और कुछ पैसा देने से काम नहीं चलेगा, उससे सम्बन्धित योजना का एक्सपेंशन करना होगा। यह अधूरा विस्तार किया गया है। पहले अंत्योदय के माध्यम से विस्तार किया गया था। यहां पर स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इंसान को भोजन करने के लिए, नाश्ते के लिए मांस मछली, हरी सब्जियां, फल कैसे मिलेंगे।[R6] रोटी के अलावा कड़वा तेल है, घी है, मसाले हैं, उनके लिए पैसा कहां से आयेगा। आप गरीब आदमी को सूखी रोटी की तरफ, लालच में डालकर, शॉर्टकट रास्ते से, बहुत जगह मैनडेट लोगों ने लिया है। यह जो 100 दिन की बात हमें समझ में नहीं आ रही है, 100 दिन की क्या हड़बड़ी है, यह हमें समझ में नहीं आ रही है। जैसा मैंने कहा कि इन नेताओं के लिए रहने वाले लोग न जाने किसको क्या सब्जबाग दिखा रहे हैं।

महोदया, जिस राज्य बिहार से मैं आता हूं उसकी तुलना दूसरे विकसित राज्यों से की जाए, मैं किसी विकसित राज्य का विरोध नहीं करता हूं। लेकिन बिहार से लिए लड़ाई, अपना स्वर और आवाज हम बराबर उठाते रहे हैं चाहे कोई भी सरकार वहां रही हो। हमारी भी सरकार थी, माननीय वीपीसिंह जी की भी सरकार थी, कांग्रेस और एनडीए की भी सरकार थी लेकिन बिहार के साथ बड़ा भारी भेदभाव हुआ है। अगर आप प्लानिंग कमीशन का डाटा देखेंगे तो अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में पर-कैपिटा लोएस्ट इनकम, लोएस्ट इंवैस्टमेंट हुआ है। हां, हाल के दिनों में जब हम लोग सरकार में थे तो अन्य राज्यों के साथ-साथ बिहार को भी मदद की। गाडगिल फार्मूले से बिहार की कायाकल्प होने वाली नहीं है। जिस फार्मूले से हम राज्यों को मदद करते हैं उससे बिहार और अन्य राज्यों का जो गैप है, जो खाई है, या तो स्पेशल केयर करके, स्पेशल ट्रीटमेंट करके छलांग नहीं लगाइयेगा या स्पेशल दर्जा बिहार को नहीं दीजिएगा, तब तक बिहार का कायाकल्प होने वाला नहीं है।

आंध्र प्रदेश और नेपाल की सीमा से लगा हुआ जो बिहार का क्षेत्र है वह पूरा एक्सट्रीमिस्ट का कोरीडोर बन रहा है, वहां नक्सली बढ़ रहे हैं। चुनाव के दौरान वहां के बहुत सारे इलाकों में हम लोग नहीं जा सके। आप भी, महोदया, जिस इलाके से आती हैं उस अधवारा के पहाड़ों पर जाने में आदमी सहमता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के साथ भेदभाव हुआ है, इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि जब माननीय प्रधान मंत्री जी बोलेंगे और जैसा हमने कहा कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दीजिए। हमारे यहां पॉलिटिकल पार्टीज में अंदर से कोई भेदभाव नहीं है। बिहार को बराबरी पर लाइये। अगर आप बिहार को बराबरी पर नहीं लाएंगे तो देश के विकास की बात जो आप करते हैं, स्वराज की बात और रामराज्य की बात आप करते हैं वह सपना-सपना रह जाएगा। इसलिए हमारे दल का यह जबर्दस्त अरमान है। सारे अखबारों में, हर जगह, आज नहीं लगातार, हर तबका, वहां की सरकार, वहां की पार्टी के लोग यही चाहते हैं। जब बिहार राज्य का बटवारा हो रहा था तो माननीय आडवाणी जी मुझे माफ करेंगे, आप लोगों ने कहा था कि हम बिहार को तकलीफ नहीं होने देंगे। मैं बिहार का बटवारा नहीं चाहते था, मैंने तो कसम भी खाई थी कि मेरी लाश पर बिहार बंटेगा। लेकिन हम लोगों को जलील करके वह हुआ। मैंने माननीय सोनिया जी से, कांग्रेस पार्टी से भी आग्रह किया था कि माननीय राजीव गांधी जी ने छोटे-छोटे राज्यों का, राज्य के बंटवारे का विरोध किया था।

आज नेपाल से बिहार आने वाली जो नदियां हैं उनसे बिहार में बाढ़ आती है। आज नेपाल की क्या हालत है। हां, हम लोगों ने स्वीकार किया था कि हम नेपाल से बात करके हाई-डैम बनवाएंगे, लेकिन अब वहां कौन सुनने वाला है। आज बिहार की जो खेती है, क्या स्थिति है? वहां बाढ़ है, कटाव है, वाटर-लौगिंग है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने गंगा नदी को राष्ट्र नदी घोषित करना स्वीकार किया है। गंगा मां हमारे बिहार को दो खंडों में विभाजित करती है - नार्थ बिहार और दक्षिण-मध्य-बिहार। नार्थ बिहार में डैंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत थिक है, ज्यादा है और बैस्ट फर्टाइल लैंड है, हर साल वहां हमारी तबाही है और रहेगी, अगर आपने वहां पर उचित ध्यान नहीं दिया। वहां पर जब तक हाई-डैम नहीं बनेगा, नदियों की खुदाई नहीं होगी, गंगा नदी के दाए-बाएं पॉपुलेशन का जो इरोज़न होता है वह नहीं रुकेगा, तब तक बिहार की तबाही होती रहेगी।

हमारे बिहार के लोग दुनिया भर से, अपनी मेहनत से, सबसे ज्यादा दौलत कमा कर देश में ला रहे हैं। लेकिन इन लोगों की क्रैडिट-डिपोजिट रेशो 33 प्रतिशत

बिहार में इंवैस्ट होनी चाहिए, लेकिन वह नगण्य है। तो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है।[r7]

महोदया, माननीय प्रधान मंत्री जी को जवाब देना है, समय की आपके पास कमी है और हम लोग इस पर, आगे भी चर्चा में भाग लेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सच्चर कमीशन ने सब जगह सर्वे किया तो पाया कि इस देश में, नौकरियों में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन इनएडीक्वेट है। बिहार में, हमारे राज में कुछ इज़ाफा हुआ था लेकिन दूसरे राज्यों में उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। सेना में भी सर्वे किया गया था कि मुसलमानों की संख्या क्या है? उस पर काफी उंगली उठाई गयी और उस मुहिम को रोका गया - यह कोई अच्छी बात नहीं है। हमने रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया। सच्चर कमीशन की जो रिपोर्ट आई और एक माननीय सदस्य ने कल ठीक ही कहा था। वे बता रहे थे कि मुस्लिम डॉमिनेटेड 90 जिलों को हम लोगों ने चुना लेकिन उनके लिए पैसा जहां भी गया, वह जमीन पर नहीं उतरा। लेकिन जहां मुसलमानों का डॉमिनेशन नहीं है, वहां के मुस्लिम समझते हैं कि हमारा चयन क्यों नहीं हुआ? रंगनाथ मिश्रा की जो रिपोर्ट है उसे हमें टेबल पर रखना चाहिए। हमारी मुस्लिम बेटियों में शिक्षा की भारी कमी है। बंगला देश, पाकिस्तान और भारत में शिक्षा के ऊपर जब समीक्षा हुई तो मुस्लिम वर्ग में महिलाएं, शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ी पाई गयी। इसलिए शिक्षा में मुस्लिम महिलाओं को जब तक रिजर्वेशन आप नहीं देंगे, समय पर छात्रवृत्ति नहीं देंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हमारी शिक्षा, हमारा विकास अधूरा रहेगा। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि हम उनको नौकरियों में आरक्षण देंगे।

इस देश में तीसरे और चौथे फेज में जो मैनडेट मिला है, उसे देखें। बंगाल, पूरा ईस्टर्न यूपी, पूरे बिहारी लोग, पूरे माइनॉरिटी के लोग साक्षी हैं कि 80 प्रतिशत लोगों ने सीपीएम को छोड़कर, प्रणब बाबू आपको वोट दिया है। ममता जी और आपके कॉम्बीनेशन को बड़ी उम्मीद से वोट दिया है। लेकिन उनके प्रति आपका क्या रवैया है? इस रवैये को आपको सामने रखना चाहिए।

जो हमारा पसमंदा मुसलमान है उसे आजादी से पहले, अंग्रेजी सरकार ने एसटी में रखा था, लेकिन जब आजादी मिली, तो जो अदर भाषा के लिंग्विस्टिक लोग थे, उनको रखा गया। लेकिन सन् 1950 के बाद जब हमने विधान बनाया तो आर्टिकल 341 में संशोधन करके उनका जिक्र नहीं किया गया। आज इंसाफ की जरूरत है और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। मुसलमान लोग कोई बाहर के लोग नहीं हैं। उस बात का जिक्र आज कहीं नहीं है, इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। उसमें हमारा सपोर्ट आपको मिलेगा, जैसे अभी तक मिलता आया है।

एसईजैड का खुमार आज भी बंगाल भोग रहा है। जो हमारी बैस्ट लैंड है, महाराष्ट्र से लेकर दूसरी जगहों तक, वह सिमट रही है, कम हो रही है। हमारा और हमारी सरकार का एसईजैड पर कोई संकल्प आना चाहिए। किसानों की खेती, एनीमल हसबैंडरी हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। आज हमारी खेती बरसात पर निर्भर है, सिंचाई का जिक्र कहीं नहीं है कि सिंचाई के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। पंजाब में आज पैदावार कम हो रही है और वह इसलिए कम हो रही है कि खाद पर खाद, फर्टिलाइजर पर फर्टिलाइजर और कैमिकल्स हम जमीन में डाल रहे हैं और हमारी जमीन पॉयजनश हो रही है, लेकिन इस पर हमारा ध्यान नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री जी और सरकार को इस पर काफी मजबूती के साथ ध्यान देना चाहिए।

माननीय प्रधान मंत्री जी, आपने जो तीन रूपये किलो वाली बात कही है वह सराहनीय बात है लेकिन जो बढ़ई है, लौहार है, सुनार है, हाथ से काम करने वाला आदमी है, कुदाल और खुरपी बनाने वाला तबका है, उस पर भी ध्यान जाना चाहिए। आज खुरपी और कुदाल टाटा बना रहा है और ये आदमी बेकार हो गये हैं और हम नरेगा में मजदूर बना रहे हैं, उन्हें 100 दिन का काम दे रहे हैं। हमारे लोग जिनका जीवन मिट्टी से जुड़ा था, आज उनके काम को मशीन कर रही है। [r8] आज वहां मशीन से काम हो रहा है। बुलडोजर से वहां मिट्टी पाटने का काम हो रहा है। मजदूर तबका वहां तबाह हो गया है। उन्हें दो-तीन रुपए किलो चावल दे कर भरमाया नहीं जा सकता है।

अध्यक्ष महोदया : आप अपनी बात समाप्त कीजिए। अभी कल्याण सिंह जी को बोलना है। 12 बजे प्रधानमंत्री जी को बोलना है। आपको जितना समय दिया था, उससे ज्यादा आप बोल चुके हैं।

श्री लालू प्रसाद : महोदया, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। अब मैं महिला आरक्षण के संबंध में कहना चाहता हूं। माननीय मुलायम सिंह ने कहा कि यह साजिश है। मैं इस साजिश का पर्दाफाश करता हूं। बैकवर्ड क्लासिस सिटीज़न आफ इंडिया, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां बननी शुरू हुई, इस देश का अभिजात वर्ग बड़ी चतुराई से मासूम महिलाओं को आगे खड़ा करके बैकवर्ड मूमेंट को डाइल्यूट करना चाहता है। शरद यादव न आए, लालू यादव न आए, न आए मुलायम सिंह और कल्याण सिंह तथा जितने भी दलों का बेस बैकवर्ड क्लासिस है जैसे डीएमके तथा जिन दूसरी पार्टियों का आधार बैकवर्ड क्लासिस है, यह साजिश है कि क्षेत्रीय पार्टियों और उनके लीडर्स को यहां नहीं आने दिया जाए। राहुल जी शायद हाउस में नहीं हैं, हम लोगों ने शुरू से कहा है कि हम महिला रिजर्वेशन का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस देश में आजादी के बाद कितनी हमारी मुस्लिम बहनें एमपी बन कर आई हैं। मिट्टी से जुड़े लोगों को, राहुल गांधी जी ने जब जिक्र किया था, तब लोग हंस रहे थे और मज़ाक में बात उड़ा रहे थे, कलावती के विषय में। हम महिला आरक्षण में कलावती को देखना चाहते हैं, भगवती देवी को देखना चाहते हैं।...(व्यवधान) आपकी कृपा से राबड़ी देवी तो हैं ही।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : लालू जी आप चेयर को संबोधित कीजिए।

श्री लालू प्रसाद : रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन हो। श्री मुलायम सिंह यादव ने हमें ललकारा - तैयार रहो। हम तैयार हैं, चौबीसों घंटे तैयार हैं। तैयार का मतलब यह नहीं है कि हाथापाई करनी है। अगर आप यह सोचेंगे कि आंकड़े हमारे पक्ष में हैं, तब हम खेत में चलेंगे, खलिहान में चलेंगे और बताएंगे कि देश में 20 रुपया आमदनी भी लोगों को नहीं है। इस सदन में हमारी बेटियां आनी चाहिए। सदन में पहले वाले होम मिनिस्टर साहब नहीं हैं। एक बैठक हुई थी और मैडम उस बैठक में थीं, इन्हें पूरी जानकारी है। आप रिजर्वेशन कीजिए 20 परसेंट या 25 परसेंट कीजिए, लेकिन उसमें कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए। दलित हैं, ट्राइबल हैं, मुस्लिम हैं, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है। बैकवर्ड क्लासिस को आप विधायक और सांसद पद के लिए आरक्षण दीजिए। जो मोस्ट बैकवर्ड हैं जैसे लौहार, बढ़ई आदि जाति के लोग हैं, जो सीधे चुन कर नहीं आ पाते हैं, उन्हें आप आरक्षण दीजिए। कई बार यहां मुहीम चली कि पूरे बैकवर्ड क्लास एमपीज़ की बैठक हुई और बैठक में तय हुआ कि हम लोगों को एमएलए और एमपी पद में आरक्षण होना चाहिए। आप महिलाओं का, हमारी बहनों का आरक्षण कीजिए, हम विरोध नहीं करते हैं। बीस लाख की आबादी पर एक एमपी बन रहा है। मेरा फिर से सुझाव है कि चाहे आप 20 परसेंट या 25 परसेंट रिजर्वेशन कीजिए, लेकिन आरक्षण के अंदर आरक्षण आप नहीं करेंगे, तो हम मानने वाले नहीं हैं। यह बात ठीक है कि लोकसभा में बैठने की कम जगह है, आप सैंट्रल हाल में चलिए। सैंट्रल हाल को लोकसभा में कंवर्ट कर दीजिए। राज्य सभा में भी सीटें बढ़ेंगी, तो उन्हें आप लोकसभा में बैठा दीजिए। राज्य सभा जब खाली होगी, तो अब जैसे सैंट्रल हाल में चाय-पानी पीते हैं, वहां चाय-पानी की व्यवस्था कर दीजिए। सैंट्रल हाल में जितनी भीड़ रहती है, उनकी संख्या आप सीमित कर दीजिए। राज्य सभा की बगल में कैंटीन भी है। आप लोग पावर में हैं, ठीक है, हम खुश हैं, इसमें कोई नाराजगी नहीं है।[I9] जो सहयोगी लोग हैं. चाहे उधर है लेकिन हम इधर हैं, सहयोगी लोगों से संबंध अच्छा रखना पड़ेगा। मैं जो लक्षण

देख रहा हूं, शुरुआती दौर ठीक नहीं रहा है, कैबिनेट विस्तार का भी मैसेज बहुत गलत गया है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः लालू प्रसाद जी अब आप अपनी बात खत्म करिए।

श्री लालू प्रसाद महोदया, आप मेरे यहां से आई हैं इसलिए कुछ तो पक्षपात करिए।

प्रधान मंत्री जी जो चाहते हैं, प्रधान मंत्री जी जो चाहते थे, मीडिया में जो सब बातें आई, मैं कोई किसी पर टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, वह बात बदल गई है, इस कारण शुरुआती दौर में मैसेज अच्छा नहीं गया है। देवी सुषमा जी को मैं सुझाव देना चाहता हूं कि वह खुल कर सामने आएं क्योंकि उमा जी महिला रिजर्वेशन के मामले में खुल कर सामने आई हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर यहां ज्यादा महिलाओं को लाया जाएगा तो उनका यहां क्या महत्व रहेगा। देश में सच्ची बात को स्वीकार करके आगे बढ़ाना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, लेकिन समय खत्म हो रहा है,, ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज Â मैं किसी के आने से असुरक्षित महसूस नहीं करती हूं इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। उनको आने दीजिए।

श्री लालू प्रसाद अगर कोई नहीं है तो आपका भाई सुरक्षा देने के लिए है। पुरानी सब बातें खत्म हो गई हैं।

महोदया, मैं धन्यवाद देने के साथ-साथ पूरी बधाई इस बात के लिए देता हूं कि नई सरकार बनी है। हमें आशा है कि वह पूरे पांच साल काम करेगी। मैं प्रधान मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि वह अपने साथियों को भूले नहीं हैं। हम लोग मंत्रिमंडल में नहीं हैं लेकिन हम लोगों ने आपको जो सहयोग दिया, उसका जो पत्र हमें भेजा, उसके लिए बधाई देते हैं। हम लोग यही चाहेंगे कि आप अपने काम में सफल रहें, सौ वर्ष और जीवित रहें और देश के लिए सौ काम करते रहें। जहां भी हम लोगों के सहयोग की जरूरत होगी, सहयोग देंगे लेकिन कुछ लोगों द्वारा हमारे साथ जो व्यवहार हुआ, मैंने आपको और मैडम को कनवे कर दिया। हम सत्ता में रहें या न रहें, हम 20 साल सत्ता में रहे हैं, गाय,भैंस और बकरी चरा कर आए हैं। हमारे बाप-दादा और हमने कभी सोचा भी नहीं था लेकिन अपमान की जिन्दगी हम जी नहीं सकते हैं। अगर कोई आदमी हमें अपमानित करेगा तो जो भी हमारी शक्ति होगी, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हम इस मामले में संविधान के साथ कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। इस तरह के लोग आपके दल में हैं और उन लोगों ने हमारे साथ जो व्यवहार किया है, लगता है कि मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं हैं। ऐसे लोगों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। बाकी हम लोगों की कोई लालसा नहीं है।

अध्यक्षा महोदयाः लालू प्रसाद जी, कृपया अपना आसन ग्रहण करिए।

श्री लालू प्रसाद अंत में मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी अंग्रेजी भी अच्छी तरह जानती हैं। उन्होंने पूर्व में आपके द्वारा तैयार भाषण को हिन्दी में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा हैं जिसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं।

***श्री हरिभाऊ जावले (रावेर) :** अध्यक्ष महोदया, माननीया राष्ट्रपति जी के भाषण में बहुत सारे सुनहरे सपने जनता को दिखाये गये। सरकार अपने अगले 100 दिनों में और 5 सालों में क्या काम करने वाली है, उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया। पीने का पानी, सिंचन, रास्ते, शिक्षा, हैल्थ, नदियों की सफाई, ऊर्जा, रोजगार सुविधा आदि सब जनता को लुभाने वाली बातें बताई गई। लेकिन यह सब करने के लिये पूरे देश में जिनकी सहायता होती है, उन किसानों के लिए कुछ कम ही दिया गया है। किसानों के लिये सिंचन की व्यवस्था होनी चाहिये, उसके लिये एनडीए सरकार ने जो नदी जोड़ योजना की संकल्पना रखी थी, उसे पूरा करना चाहिये। किसानों के लिए ऊर्जा, रासायनिक खादों की उपलब्धता, उनके उत्पादनों को किफायती भावों में लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। मतदाता क्षेत्रों की पुनर्रचना के बाद ग्रामीण मतदाता क्षेत्रों में गांव बंटे हैं। उनका एरिया बढ़ा है। सांसदों को जो निधी (एम.पी. फंड) मिलती है, वो सिर्फ दो करोड़ मिलता है, उस निधी में पचास गांवों का भी काम सांसद कर नहीं सकते। मेरी मांग है कि सांसदों की निधी (एम.पी.फंड) पांच करोड़ करना चाहिए ताकि पूरे मतदाता क्षेत्र में काम कर सके। धन्यवाद।

* Speech was laid on the Table.

*SHRI J.M. AARON RASHID (THENI): Our UPA government under the auspicious guidance of Madam Sonia Gandhi Ji and Hon'ble Prime Minister Dr. Man Mohan Singh ji's initiative and good efforts have given priority for Consolidation of Flagship programmes like energy and Jawahar Lal Nehru's Urban Vision, Amendment Bill to Land Acquisition Act etc., Implementation of SC & other forest Dwellers Rights Act. Prime Minister's 15 point programme for the welfare of minority community have brought a clear vision of our government, the way how our government is interested in working for the improvement and protection of the poor & downtrodden. One should know 15 lakh houses have been constructed so far for the urban poor at a cost of 50,000 crores during the last 4 years and every BPL family in rural and urban areas will get 25 kgs of rice or wheat @ Rs. 3 per kg. The aim is to eradicate hunger and hunger deaths. The literacy level of the people have raised. Gents 75% and ladies 54%. And government is taking steps to recast the National Level Mission to form a separate National Mission for female literacy. It is to be appreciated that every woman will be a literate one in the next 5 years. In order to improve rural infrastructure, our Governemnt has launched Bharat Nirman. Basic Necessity to improve the required infrastructure at village level like improving roads, electricity security, water, sewarage, telephone and housing. It really shows that the government's enthusiasm towards the needy poor people's importance and their improvement in the civil society has been properly taken care of only by our Congress led government under the auspicious guidance of Madam Sonia Ji. Though the minorities are lacking behind in education, cultural, civil improvement, business and no proper financial assistance by bankers and in government jobs. In

* Speech was laid on the Table

our Hon'ble Prime Minister's 15 point programme direct letters to all district Collectors of our country have risen the eye brows of all the officials who are not properly implementing this 15 point programme for the minorities. Properties of Muslim wakfs lakhs and lakhs are occupied by the Government, Semi-quasi government. First our government should have to take steps to collect proper rent from the occupiers who ever they may be, how big position they may hold.

Land Acquisition Act, rehabilitation & Resettlement Bill clearly indicates that the protection to the Farmeres given by our government has been welcomed by all the farming community irrespective of Religion. Thanks to our government for enhancing social security covers to the people above 65 years of age and handicapped people. I request our government that social security & old age pension should be reduced to 60 years instead of 65. I appreciate our government's efforts to pass the 1/3rd woman's resevation bill and the constitution amendment bill to provide 50% reservation to women & local bodies. In NRGEA, working period of 100 days in a year have to be extended to 150 days and the daily salary increased to Rs. 100/- to avoid malpractices by the concerned authority like Panchayat Presidents/officials. I appreciate that District Level committees will be constituted. My humble suggestion to our government is that we are giving 100 days work to BPL card holders. The Card holders should open bank account to avoid Panchayat officials, Presidents, grabbing the hard earned money of the poor persons. Or directly given to the bank to avoid middle man's cheating. I appreciate the setting up of delivery Monitoring unit at Prime Minister's Office to monitor flagship programmes and ICONIC projects & projects for Railways, Power, Highways, Port Rural Telecom. Our Government should encourage private/public partnership to avoid government's direct investment. BOT policy should be adopted. In Kerala every year 2500 TMC water is going waste to the sea. In Mullai Periyar river having 136 feet height with 12 TMC capacity. Supreme Court has given an order to increase to 142 feet which is not implemented so farâ€¦.. What action our government is going to take against the Kerala Govt.

What is the Constitution legality of Supreme Court's order for not obeying by the Kerala government. When the People of India's dream for protected drinking water to every one will be fulfilled. When our government is going to link the River waters and when the government will nationalize the same. I urge upon the government to nationalize the river waters in

the large interest and unity of our country. I appreciate our Hon'ble Prime Ministers bold steps and courage for signing the Nuclear agreement with US and passing the same in the Parliament when the communites threatened to withdraw support. Our Nation's image and our Prime Minister's leadership has been elevated in the eyes of the whole world. Sir in North Eastern States such as Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Manipur, Jammu & Kashmir, we have about 1 lakh mega watt Hydro Electric Producing Capacity which has to utilize so that we can supply electricity uninterrupted to the people by not spending more money in coal Thermal and in civil nuclear plants also. In hydro electric power the production cost is only 50 paise where as in Nuclear production the cost is more. Our government have set up a separate Mission like National Mission on Energy, National Water Mission, National Mission on sustainable agriculture. Similarly government has to form a National Mission on Hydro Electric Producing Commission.

Lastly but not the least Sir, our government clearly indicates their full support to the Tamils of Sri Lanka. Sir, they have to enjoy the equal rights what Singhalese are enjoying in that country.

Government of India should not allow any discriminations as in Sri Lanka. The Tamils have to lead a life with self respect and dignity. Some outfits in Tamil Nadu are spreading rumours that our government is not doing anything for them and also some people's inflammatory speech. I urge upon the government to initiate action against those who are working against the soverignty and integrity of our nation and rule of law should be implemented against those who are trying to malign the interest of our country for petty gains by spreading these types of anti national rumours. With these words I conclude my speech.

श्री कल्याण सिंह (एटा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि सदन की सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। मैं माननीय करिया मुंडा जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि सर्वसम्मति से सदन के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कुछ कहने का समय दिया। मैं जानता हूं कि समय कम है इसलिए बहुत कम समय में केवल एक ही इश्यू के बारे में बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। यहां बहुत कुछ कहा जा चुका है, मैं उसे नहीं दोहराऊंगा। मेरा मुद्दा कि सामाजिक न्याय को अमली-जामा पहनाने का है। सामाजिक न्याय की मोटी-मोटी परिभाषा है - दबे, कुचले, उजड़े, पिछड़े, दलित, शोषित, पीड़ित और युगों से वंचित वर्गों को सत्ता, व्यवस्था, विकास, राजनीति और राष्ट्र निर्माण में सम्मानजनक और पारदर्शी हिस्सेदारी देना है। इस संदर्भ में महिला आरक्षण का प्रश्न महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाÂषण में 33 परसेंट आरक्षण विधानमंडलों और संसद में देने का जिक्र किया है। सरकार की भी यही मंशा है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। अगर आवश्यकता पड़े तो 33 परसेंट से बढ़ाकर और ज्यादा आरक्षण महिलाओं को दिया जाना चाहिए क्योंकि देश में महिलाओं की जनसंख्या 50 फीसदी के आसपास है। कोई भी देश या समाज इस 50 प्रतिशत आबादी को उपेक्षित करके आगे नहीं बढ़ सकता है। यही कारण है कि आजादी के 62 साल बाद भी अभी तक महिलाओं को वह तरक्की, प्रगति और सम्मान नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था। 33 परसेंट आरक्षण की बात कही गई है सिद्धांततः मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अमलीजामा पहनाने के परिप्रेक्ष्य में मेरा कहना है कि 33 परसेंट आरक्षण में पिछड़ी जातियों, अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, अर्थात कोटा के अंतर्गत कोटा का प्रावधान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो केवल अभिजात वर्ग के 15 प्रतिशत का जो सामाजिक वर्ग है, वही लोग सत्ता, व्यवस्था और राजनीति में हावी होंगे और 85 प्रतिशत समाज फिर से अधिकारों से वंचित रह जाएगा। वह न सत्ता में आ पाएगा और न ही राजनीति में अपना वर्चस्व कायम कर पाएगा। यह सामाजिक न्याय का सिद्धांत है। आज का मुद्दा ऐसा है जिसे सबको स्वीकार करना चाहिए। मैं कहूंगा कि जो भी पार्टियां या माननीय सदस्य सामाजिक सिद्धांत के पक्ष को ठीक मानते हैं, यदि सामाजिक न्याय से सहमत हैं, उन्हें पार्टी लाइन से ऊपर उठकर आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण की मांग करनी चाहिए, इसका समर्थन करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे बहुत गहरी साजिश काम कर रही है। मैं यह कहने के लिए क्षमा चाहूंगा - चाहे सत्ता में बैठे लोग हैं, चाहे विपक्ष में बैठे हैं कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है ताकि पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को सत्ता से दूर रखो, राजनीति से दूर रखो और विकास से भी दूर रखो। इसके बहुत दुÂष्परिणाम होने वाले हैं। अगर आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण नहीं दिया गया तो इससे समाज में बहुत कटुता पैदा होगी। मुझे यह बात समझ नहीं आती कि इसमें आपत्ति किसी को क्यों हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण करना, ठीक नहीं है।

माननीय राजनाथ सिंह जी मेरे सामने बैठे हैं। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 27 परसेंट ओबीसी के आरक्षण को तीन हिस्सों में बांटा था। 5 परसेंट में यादव रखे गए थे और शायद 9 जातियां 8 परसेंट में और शेष जातियां 14 परसेंट में रखी गई थी। अगर उत्तर प्रदेश में आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण उचित था तो माननीय आडवाणी जी बता दें कि यहां दिल्ली में आरक्षण में आरक्षण क्यों अनुचित हैं। मैं जब भाजपा में था तो इस विषय को बार-बार उठाया करता था लेकिन उस वक्त मेरी किसी ने बात नहीं सुनी थी। आज मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत गहरी साजिश काम कर रही है। मैं डरता हूं कि कहीं यह साजिश कोई दूसरा रूप न ले ले। समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। यह 85 बनाम 15 परसेंट की लड़ाई है और 15 परसेंट के लिए सब को हौब किया जा रहा है। इसे समाज स्वीकार नहीं करेगा। वह संघर्ष का रास्ता अपनाएगा। इसलिए कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे कोई संघर्ष का रास्ता न अपनाए। सरकार चाहे तो इसे कर सकती है। सरकार इसमें कोई प्रावधान करे। मुझे समझ नहीं आता कि इसमें क्या दिक्कत है? आप पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों को हिस्सा क्यों नहीं देना चाहते हैं? इसके पीछे क्या नीयत है?

मैं शरद यादव जी से एक निवेदन करना चाहता हूं, वह बुरा न मानें। वह एनडीए के संयोजक हैं। अगर एनडीए में आज कोई बड़ी शक्ति भाजपा के बाद अगर किसी की है तो उनकी है। वह एनडीए को क्यों तैयार नहीं करते, क्यों भाजपा को तैयार नहीं करते, क्यों आडवाणी जी से यह बात नहीं करते हैं? अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो वह किस बात के लिए इनके साथ हैं? ईमानदारी का तकाजा यह है शरद जी, अगर सामाजिक न्याय को अमली-जामा पहनना चाहते हैं तो एनडीए से दो-टूक कहना पड़ेगा कि या तो आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण का समर्थन करो अन्यथा हमें विदाई दो। माफ करिए बातों से काम नहीं चलेगा। वक्त आ गया है। बहुत दिनों तक समाज को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। शोषण बहुत हो चुका है। हम लोग बहुत मुश्किल से 25-30 और 50 साल बाद यहां आ पाए हैं। अब फिर हमें सौ साल पीछे धकेला जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर) आप कांग्रेस से समर्थन क्यों वापस नहीं लेते हैं? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप कृपया बैठ जाइए। माननीय कल्याण सिंह जी, आप इधर संबोधित करिए।

श्री कल्याण सिंह : महोदया, मैं पुनः आपके माध्यम से सदन, सरकार और विपक्ष से मांग कर रहा हूं कि सामाजिक न्याय की खातिर अपना दिल चौड़ा करिए, विचारों को उदार बनाइए। उजड़े, पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक और आदिवासी महिलाओं को भी हिस्सेदारी दीजिए। कोई जेब से नहीं जा रहा है, जो 33 प्रतिशत दे ही रहे हो तो यदि आवश्यकता पड़े तो उसे 50 प्रतिशत कर दीजिएगा लेकिन अगर पिछड़ी जातियों को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों को अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं होता है तो समाज के साथ यह बहुत बड़ा धोखा होगा और धोखे के खिलाफ जनता फिर सड़कों पर निकलेगी। मैं नहीं चाहता कि जनता सड़कों पर आए। इतनी बात कहकर मैं आपको पुन: धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया।

*SHRI D.V.SADANANDA GOWDA(UDUPI-CHIKMANGALUR): After the new mandate by the people of the country UPA has placed as ruling party with much expectation. Even after 62 years of Independence our country has not served to the people for their basic needs like drinking water, saniation, housing, roads, schools in the remote villages of the country. It is the right time to reach to the poor people of the villages and serve the needs of the those people without any delay.

I think that much importance should be given to farmers, fisherman, weavers and labourers who are struggling for their existence even now. I would like to draw the attention of the Government in this regard. The loan waiver scheme during the year 2007-08 has not reached to the agriculturists at all. Especially the farmers in Karnataka have not benefited out of this as the Karnataka Government had a scheme of loan and interest waiver earlier to the extent of Rs. 25000/- in place much before the scheme announced by the Central Government. Hence it is the duty of the centre to reimburse the said amount to the State of Karnataka to a tune of nearly 2500 crores.

I would like to draw the attention of the Government with regard the problem faced by the Coffee growers. As the International market is fluctuating one and the coffee plants are being affected severely by borer disease the total coffee industry is suffering and if the Commerce Ministry does not come to the resuce of the coffee growers, the whole industry will be at the verge of closure. I have made this request with the earlier government with all statistics & details and the Commerce Minister promised to come to the resuce of coffee planters but nothing has come out so far. I earnestly request the Government to have a Special Package of loan waiver for coffee growers in the forth coming budget.

* Speech was laid on the Table

The Presidential address has never come out with any help to the Fisherman community of the country. We have nearly 3000 Kms sea-belt and more than two crore people live out of fishing. The practical difficulties of fisherman have not been studied properly by Governments in power and the helps needed are not given to this large section of society.

Sea-erosion is one of the problems that the fisherman families are facing. Thousands of houses are washed away by the sea every year. The plans and programmes in this regard are only in speeches and on papers. The coastal Karnataka is having 300 KMs sea bay and every year hundreds of acres of lands are being damaged, thousands fisherman houses are taken by the sea. Since 1998 project proposals costing Rs. 138 crores are sent by Government of Karnataka to the centre are pending before the Water Resources Department in cold storage. Several delegations and discussions in the matter are all of no use and still the fisherman's families are suffering from the said problem without any rescue by the Centre. I urge the Government to take up this matter as this is a serious in nature.

Naxalism is the greatest problem we are facing today. The tribal and other people residing in and around remote areas are troubled by the extremists. Districts like Chikkamagalur, Udupi, Dakshina Kannada in Karnataka in Western Ghat region is the hum for naxal activities. Both reforms and stringent actions are the need of the hour. The centre should give all sorts of assistance to curtail the activities of naxalities.

Totally the next five years is a challenge for our country to become of the developed countries of the world. We all should join hands in this challenge. Political commitment and National agenda should be our plan of action. Hope that we will succeed in our intention to build our country to the expectations of the people.

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): Hon. Speaker Madam, I thank you for giving me this opportunity. I welcome the Address given by the President of India to our Parliament, but let me begin by congratulating you.

Madam, I think, when we analyse and comment on the remarks made by Her Excellency the President of India, we need to

lay the context and the context is the historical verdict, the mandate that the UPA Government has been given by the people of India. The people of India have chosen hope over hate; the people of India have preferred moderation over radicalism; the people of India have voted for inclusive governance and inclusive welfare over exclusive growth; the people of India have voted for inclusive politics over divisive politics; the people of India have chosen 'Bharat Nirman' over 'India Shining'. I think, this verdict marks an inflection point in our polity, the inflection point which, I hope, will be carried forward.

The faith the people have put in the Congress Party under the leadership of Shrimati Sonia Gandhi, the hope the people of India have put in the ideas of Shri Rahul Gandhi is significant because the young, for the first time, have participated in this mandate and we need to respect that. I welcome the remarks of the hon. President. Since we have very limited time, I am not going to repeat some of the things that the hon. President has said and we all welcome those things.

I think, I will just point out two or three things which I do feel are imperative to make sure that we honour this historical mandate. Overall, I welcome the ten broad areas of priority that have been outlined. We need to continue our march towards socialistic agenda, which means not only increasing the expenditure in the social sectors – education, health and rural infrastructure – but also increasing the social security net that we provide to the less privileged, to the vulnerable in our country.

We also need to make sure that the governance reform, which - I think - the young and the restless of our country are very keen to make sure that we carry forward, is done. Respected Madam, I must point out that governance reform is nothing new. We have talked about governance reform before also. In fact, today morning I was reading an article by Shri Vivek Debroy wherein it was pointed out that since 18.12.2004, there have been 73 commissions which have been set up on the issue of governance reform and they have made suggestions also. But still we find that our country, especially the young, mistrust the delivery mechanisms, the Government mechanisms, the Police and the Administration. Why is this? We are running out of time. Let us get it right this time. I think, that is one of the key things that our Government needs to ensure as we go forward.

The second issue that I want to quickly make my suggestions is on agriculture. अध्यक्ष महोदया, जो आज हमें यह एतिहासिक जीत मिली है, हिन्दुस्तान के किसान का इस जीत में बहुत बड़ा योगदान है। मैं कहना चाहता हूं कि पहली बार लोगों ने वादे किए। लोगों ने कहा कि कर्जे माफ करेंगे और जितने वादे किये, उसके बीस प्रतिशत भी कर्जे माफ नहीं किये। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने कोई वादा नहीं किया लेकिन किसान की हालत श्रीमती सोनिया गांधी जी ने देखी और देश के किसान के 72000 करोड़ रुपये के कर्जे माफ किये। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमें जो वर्डिक्ट मिला है, इसमें किसान का बहुत बड़ा योगदान है।

* Let me begin by laying the context in which we all find ourselves in this august house discussing the remarks made by her Excellency. The context is provided by a decisive mandate in favour of the congress party and the UPA. I believe this verdict is no ordinary verdict, for it to me symbolizes an inflexion point in our polity, a shift from divisive polity to progressive polity. The people of India have preferred the politics of hope over the

---

* â€¦.* The part of the speech was laid on the Table.

politics of hate; moderation over extremism. The fruits of our post-liberalization growth for the first time are now reaching our villages, the smaller cities, the weaker sections, and people have attested that with this mandate. The Congress party in the leadership of Smt. Sonia Gandhi and Dr. Manmohan Singh has been able to change the rules of the game in real sense.

So when I heard Her Excellency's remarks the other day, I heard them in the backdrop of this historic mandate. And I do feel her remarks do promise to carry forward the socialist agenda to bridge the differentials that still plague our nation.

While welcoming all parts of her Excellency's speech without pointing them out to save us time, let me put forward some other suggestions that I feel may also be taken up -

Overall:

I welcome the emphasis on continuing with the socialist agenda - to expand our expenditure towards all the social sectors,

including education, rural infrastructure, and health; and to enhance the social security net for our citizens in circumstances of vulnerability.

In times of shrinking availability of global capital, providing increased and abnormal government expenditure in Infrastructure is the most normal thing. Although I do not hold a high opinion of the stock markets in this age of "exaggerated exuberance" as Alan Greenspan put it, I am sure plans to use innovative financing and public budgeting for the infrastructure has made the people on dalal street happy.

Now the next big question for 2009 is: how much higher government spending can we afford to stimulate demand, while ignoring the any increase in deficit?

I welcome the ten broad areas of priority that were outlined.

Governance reform is critical:

But this is not something new

Bibek Debroy points that from the beginning 1812 till 2004 there have been 73 reports by various commissions on the subject of administrative reforms.

This time let's get it right, no matter what it takes for we are a nation of young and restless

The people may have voted for more of the same, but they also have voted for bringing more change.

Agriculture holds the key:

Credit:-

Loan Waiver historic, but we need to follow-up steps to the loan waiver to make our approach more comprehensive.

We need to reward the Farmers who have paid in time with interest relief. Let me point out that this is also promised in the Congress Party's manifesto.

We need to free the farmers from the clutches of private money lenders by converting their loans into co-operative bank loan.

We need to allow farmers raise credit against warehouse receipts.

We also need to reduce credit rate to 4% from the current 7% (manifesto), and simplify the credit chain – by reducing the intermediaries, removing redundant conditions and guarantee requirements.

Time has come for us to consider banning the land auction law in India.

To begin with, instead of mortgaging total cultivable land holdings of the farmers only collateral tangible security may be taken.

Subsidy:-

Time has come for us to consider direct cash transfer of subsidy to the farmers. Subsidy based on crop and the size of land holding.

We are going to have 96,000 Crores in fertilizer subsidies in the 2008-09 estimates. Urgent need to fix this situation

Fixing price – 5000 Crores

MSP:-

Historic increase in the MSPs of various crops played an important role in securing our mandate.

Swaminathan Commission and the standing committee on agriculture recommendations of MSP should be taken up specifically:

C2+50% premium should be used in fixing the MSP

Also, CACP Cost calculation should be altered to cater to regional differentials (cost of irrigation, labour, and land) and should also include cost of marketing and transport.

Export policy should be framed while keeping the farmer in mind.

Research:-

I seek more funding for ICAR, Agriculture Universities to deal with issues like Climate Change with an aim to usher in a second green revolution.

For Haryana:

"One size fits all" approach of planning commission is utterly flawed.

BPL: Poverty can never be assessed in absolute terms, should always be calculated in real terms. The BPL needs to be defined on a state by state basis, measuring the cost of living in that particular state.

Bharat Nirman: We are being penalized for our last mile connectivity and rural electrification. Thus states like Haryana need some other specialized financing mechanism to participate more in flagships programmes like Bharat Nirman.

NREGA: Higher market wage expectations are rendering NREGA ineffective.

Therefore, we need more tailor made schemes to fit our needs.

One pension one rank - is a welcome step, need to expedite the implementation.

We need to expedite the construction of upstream dams on river yamuna, namely, the Renuka, Lakshar Vyasi and Kisau Dams, to ensure that we tap into the surface water that flows to the bay of Bengal each year towards irrigation in states like Haryana.

We need to solve inter-state issues pertaining to water channels expediently.

NCR region should be given special package for the upcoming commonwealth games. 10,000 Crores has been allotted to Delhi, I seek only 5,000 Crores towards the NCR planning board. How can we ignore the differential we are creating by pumping more money into Delhi and ignoring anything that lies outside its boundary? The verdict is for inclusive development; let is also include NCR area from Haryana in the development of Delhi as well.*

***श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर) :** मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करती हूं, जिसमें देश की अखंडता एवं सुरक्षा के साथ-साथ सभी वर्गों की परेशानियों को ध्यान में रखा गया है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सिंचाई, गरीबों को खाद्य सुरक्षा, महिलाओं को 50औ आरक्षण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन, अल्पसंख्यक कल्याण, आंतकवाद एवं सुरक्षा आदि अधिकतर सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है, जिनसे लोगों में आशा की एक किरण जागी है।

इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहती हूं कि इन महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए देश की आर्थिक स्थिति को देखना भी जरूरी है। मौजूदा आर्थिक हालात में धन जुटाना बड़ी चुनौती है। आज बेरोजगारों को नौकरियां देना अर्थव्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसलिए सबसे पहले राजकोषीय घाटे को रोकना भी महत्वपूर्ण है।

देश में आतंकवाद व सुरक्षा का मुद्दा भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसलिए इन मुद्दों पर सभी दलों व Specialists से राय मशविरा कर कानून बनाकर आतंकवाद को रोकना व देश को सुरक्षा देना जरूरी है। मैं याद दिलाना चाहती हूं कि जब पिछली यू.पी.ए, सरकार को परमाणु करार के कारण संकट आया, तब हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव व श्री अमर सिंह साहब ने देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं Scientist श्री ए,पी,जे, अब्दुल कलाम से राय मशविरा कर सरकार को संकट से बचाया था। हमारी समाजवादी पार्टी ने हमेशा साप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए सरकार का साथ दिया। भविष्य में भी देश से आतंकवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए हर तरीके से सहयोग देगी।

आज किसान और खेती उपेक्षित है, जबकि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। महंगाई के कारण देश में खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है। यही कारण है कि दुनिया में सबसे अधिक भुखमरी के शिकार एक चौथाई लोग भारत में रहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भूखे के लिए खेती को भगवान मानते थे। इसलिए किसानों

को सुविधाएं दी जाना जरूरी है, किसानों को 4औ वार्षिक ब्याज दर पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाये, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिया जाए, कृषि योग्य भूमि का जबरदस्ती अधिग्रहण न हो, सिंचाई के साधनों का इन्तजाम मुफ्त हो तथा राष्ट्रीय जल नीति बनायी जाए।

सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कम मजदूरी एवं अनियमित रोजगार के कारण मजदूरों की हालत अच्छी नहीं है। समाजवादी पार्टी " काम " के अधिकार को मौलिक अधिकार मानती है और काम न मिलने पर बेकारी भत्ता दिये जाने की समर्थक है।

* Speech was laid on the Table

सरकार विशेष जोखिम के दायरे में आने वाले व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा देने के मुद्दे पर विचार करना चाहती है , इसके लिए सरकार को किसानों की कर्ज माफी की तर्ज पर ही बुनकरों एवं बीड़ी मजदूरों का विद्युत बकाया माफ करना चाहिए एवं विशेष पैकेज देना चाहिए।

रिक्शा चालक, ठेले वाले, फल वाले, समान ढोने वाले मजदूर भाईयों आदि को सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा योजना एवं रिक्शा आदि साधनों को खरीदने के लिए सब्सिडी एवं पैकेज आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

फिल्म इंडस्ट्री में लाखों लोग मजदूरी कार्य करते हैं जैसे - कैमरा स्टैण्ड उठाने वाले, स्टेज को सजाने वाले, फर्नीचर का समान उठाने वाले आदि, लेकिन उनको सरकार की ओर से सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं , जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जबकि फिल्म इंडस्ट्री से करोड़ों रूपये का राजस्व भी सरकार प्राप्त करती है। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए भी विशेष सुविधाएं दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बुरी हालत है। लोगों को बिजली नसीब नहीं हो रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र रामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में सब-स्टेशन बनाये गए है वह बन्द पड़े हुए हैं। गांवों में विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है। जहां विद्युतीकरण हो गया है, वहां भी विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं हो पा रही है। ग्रामीण स्तर पर उद्योग धन्धे पूरी तरीके से बन्द हो गए हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को राष्ट्रीय महिला मिशन के रूप में पुनर्गठित करने का सराहनीय कार्य किया है, लेकिन सरकार द्वारा लड़कियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से पढ़ाई बी.ए. तक मुफ्त हो, इण्टरमीडिएट पास होने पर ही लड़की को उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार में चलायी गयी " विद्या धन " योजना की तर्ज पर पूरे देश में इसे लागू किया जाए।

जहां सरकार अल्पसंख्यकों , पिछड़ों एवं अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाने की बात करती है, वहीं उसे चाहिए कि पिछड़ा वर्ग, मुसलमानों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करे और सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं तथा मेडिकल कालेज व आई. टी . आई . आदि में शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था पूरी तरह से लागू की जाए।

मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि अपने अभिभाषण में उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के विकास के पहलू को छुआ है।

महामहिम जी का चिंतन ग्रामीण भारत के समग्र विकास पर केन्द्रित है। इस विषय पर मैं अपने अनुभव बांटना अपना कर्त्तव्य समझती हूं।

भारत सरकार को गरीब निर्धन सिनेकर्मी, मजदूर जो असंगठित क्षेत्र के हैं, उनके विकास के लिए रोजगार पूरक विकास योजनाएं एवं सहायता के लिए अनुदान की व्यवस्था करना आवश्यक है। विशेष आर्थिक पैकेज स्वास्थ्य केन्द्र - बीमा योजना, आवासी योजना- अच्छे स्कूल एवं ऋण की सुविधा देनी चाहिए।

महिलाओं का आरक्षण ओ.बी.सी. , एस.सी. एस.टी. के अनुपातिक आधार पर हो।

असंगठित क्षेत्र में पत्थर तोड़ने वाले मजदूर जो विंध्याचल या राजस्थान की पहाड़ी में पत्थर तोड़ते हैं अनुसूचित जनजाति आदिवासी हैं। पत्थर तोड़ने समय निकलने वाले सिलिका से टी.बी. रोगी हो जाते हैं। युवा अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लड़कियां युवा अवस्था में विधवा हो जाती हैं। जंगलों से लकड़ी बीन कर लाती हैं। बाजार में बेचती हैं। तब जाकर घर में खाना बनता है। यह दशा चित्रकूट मानिकपुर उ,प्र, विंध्याचल पर्वतमाला में देखी जा सकती हैं। इन विधवाओं और उनके परिवारों को स्वास्थ्य ,रोजगार, पेयजल और शिक्षा तथा आवास हेतु आर्थिक पैकेज जारी किया जाए।

सरकार को शासन व्यवस्था में सुधार करने के लिए जरूरी है, कि पहले लोगों के दिलों की आवाज को सुने और फिर सुधार करे। यह आम लोगों की धारणा है कि सत्ता में बैठे लोग देश भर में न केवल अपने राजनैतिक विरोधियों का, बल्कि तमाम निर्दोष गैर राजनैतिक व्यक्तियों का भी उत्पीड़न कर रहे है और सरकारी मशीनरी का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग किया जा रहा हे।

देश में साप्रदायिक सद्भावना को स्थापित किया जाना जरूरी है, क्योंकि आज सरकारी नीतियों के कारण एक ऐसा माहौल बन गया है, जहां चारों ओर लूट ही लूट है। देश में अहिंसा की जगह हिंसा आत्म सम्मान की जगह चाटुकारिता, भाईचारे की जगह नफरत , सादगी की जगह विलासिता ने ले ली है। सारा देश सत्ता के संरक्षण में अराजकता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए हम सबको धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के प्रति निष्ठा रखते हुए देश के गरीब वर्ग के लिए कार्य करना होगा।

THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH) : Madam Speaker, I join all other Members of this august House in conveying our very sincere thanks to the Respected Rashtrapatiji for a very thought-provoking Address. I would also like to take this opportunity to thank the Leader of the Opposition, Shri L. K. Advani, other senior Leaders including Shri Mulayam Singh Yadav, Shri Lalu Prasad and many other distinguished personalities who have spoken on the Address of the hon. President.

I sense an underlying sense of unity is what our Republic is about. What are the tasks that lie ahead and how we should go about in achieving those objectives? Shri Advani had said that we should all work to make the 21st Century the India's Century. This is an idea that I have been stating for quite some time. I said as early as 1991 quoting Victor Hugo : "That no power on earth can stop an idea whose time has come" and I sincerely believe that the emergence of India as a major power house of the global economy and global polity happens to be one such idea whose time has come. It is our privilege to contribute to the realisation of this cherished goal of our country.

The tone of speeches on all sides has been highly constructive, and I think this augurs well for our country starting with the unanimous election of hon. Speaker followed by unanimous election of hon. Deputy Speaker. We have made a new beginning. It is my hope and prayer that we maintain that spirit of bipartisanship when it comes to dealing with large number of National problems and concerns, which we face as a country.

Madam, the conduct of free and fair elections and the subsequent formation of the Government are indeed a triumph for Indian democracy. We can take legitimate pride in our achievements. There were many people who believed that Parliamentary democracy cannot succeed in a country as poor as India, and that Parliamentary democracy cannot succeed in a country where the voters are illiterate to such an extent as is the case with our country. We have seen people writing about it. I recall that way back in the 1960s a correspondent of the *New York Times* Selig S. Harrison, who was based in India, went back and wrote a book, namely, India : "The Most Dangerous Decades", predicting the demise of Indian Union by the end of the 1970s.[r10]

We have proved all these prophets of doom and gloom wrong, and our Republic has shown the resilience to march ahead.

Madam, I sincerely believe that social and economic transformation of India in the framework of a democratic polity, an open society committed to the rule of law, committed to respect for all fundamental human rights, is a development in world history which, if it succeeds, will have profound consequences for the processes of development in all countries of the third world.

People marvel at a country of a billion people characterized by vast diversity of languages spoken, characterized by diversity of religious beliefs and caste tensions, yet moving forward together. This is something which has earned our country deep admiration. At least, that is what I have sensed in my five years as Prime Minister as I travelled in various parts of the world.

It is our privilege and it is our bounden duty to strengthen the democratic foundations of our magnificent Republic.

There are tensions in the system, and while we congratulate ourselves, we must not lose sight of some manifest weaknesses – the growing use of money power, muscle power in elections. I think these are developments which need to be tackled, if we have to maintain the health of our democratic polity.

Also, if we have to succeed, it is necessary for us to take a firm pledge that we will not encourage groups and individuals who wish to divide our country on the basis of religion or caste.

We should deal firmly with people who believe violence is the only way to achieve their object. I believe we must all be solemnly committed to ensuring that social and economic development, which is a must for a poor country, must benefit all sections of society, all States of the Union, all communities and all persons.

I heard, Lalu ji refer to the special problems of Bihar. I assure him and I assure the hon. Members that the backward regions of our country, those which have been left behind in the race for development, will claim our priority attention as we deal with the challenges of development.

There is one thing more that I wish to say. Democracy is a beautiful tree, but all modern democracies, under the pressure of competitive politics, tend to adopt a short-term perspective; very often, longer term concern and issues do not get the attention that they deserve. We must have this long-term vision, if India is to realize its development objective. I sincerely hope that we will have that vision, that will and the courage to address some of these longer term concerns as a befitting tribute to the founding fathers of our Republic who gave us the magnificent Constitution of India.[r11]

Madam, the mandate that our Government has received, and we accepted in all humility, leaves no scope for bragging about. We recognise that this mandate casts a heavy responsibility on all of us to give our country a strong, purposeful Government, a stable Government, a Government committed to the pursuit of inclusive development process. As the President herself has acknowledged in her gracious Address, this is an agenda which will keep us all busy every day of the next five years. The mandate, therefore, is a mandate for stability, of change with continuity, commitment to inclusive growth, equitable development and commitment to the preservation and protection of a secular and plural India.

Madam, we will consolidate our efforts on each of these fronts and the President's speech has outlined the direction we intend to pursue. We will further strengthen our flagship programmes for employment, education, rural and agricultural development, health, and improve the delivery of public services through greater transparency and accountability. We are aware that though much ground has been covered, a lot more remains to be done. We will spare no effort in accelerating the speed of our work.

Madam, in this gigantic task I recognise that no development agenda can succeed if the Centre and the States, and now the third tier Panchayati Raj institutions, do not work in a spirit of collaboration, in a spirit of harmony. Madam, you have my assurance that in dealing with States, in dealing with Panchayati Raj institutions, we will operate strictly on the basis of objectivity. No discrimination will be done against any State which may not be governed by parties which are in power in Delhi. This is a commitment I give. I call upon all Chief Ministers to work together in the National Development Council to earnestly implement the vast development and inclusive development agenda that the President has placed before our people.

Madam, I should say a few words about the strategies and programmes that President in her speech has referred to. What is our fundamental task as a Government? I have always believed and here I draw inspiration from the founding fathers of our Republic Mahatma Gandhi, Jawaharlalji, Indiraji, Rajivji who have always emphasised that our freedom will be incomplete so long as there is mass poverty in our country.[KMR12]

It was the dream of the father of our nation, Mahatma Gandhi to wipe out tears from the eyes of each and every individual in our country. That is an ambition which we may not be able to fulfil but that is the inspiration which should and which will guide our Government in its quest for giving our people a life of dignity and self-respect.

Development is meaningless if our people suffer from ill-health, if our people are illiterate, if the environment protection measures are not in place, if the degradation of land and water resources of our country and the river resources of our country goes unchecked. Therefore, we commit ourselves to this inclusive vision for development where the fruits of development will be equitably shared, where all individuals in our magnificent Republic would get an equal chance to fulfil their ambitions. It is not easy but I am convinced that education, health and environment protection are the means through which we can help our people to improve the quality of their living. But all this requires resources and money does not grow on tree. If we have to invest in our flagship programmes, then we need lot more resources and expanding tool of resources. Fortunately, in the last five years, our economy managed to grow at the rate of 8.6 per cent. That benefited our revenues enormously. We were able to expand the resource flows for agriculture, for rural development, for education, for health and for environment protection.

More recently, particularly in the last one year because of the international slow down our economy has been affected. Our growth rate which was about 9 per cent, in the previous four years has declined to about 7 per cent. We live in an increasingly inter-dependent world economy and I cannot promise you that we will not be affected by global events but I am convinced since our savings rate is as high as 35 per cent, given the collective will, if all of us work together, we can achieve a growth rate of 8 to 9 per cent even if the world economy does not do well. This shows we will maintain, at least, 7 per cent growth rate. In the short run, we cannot do better but this is not good enough. Therefore, the ambition that our Government has is that notwithstanding developments in the global economy, our country must have the resilience to so manage its affairs that it grows at the annual rate of 8 to 9 per cent. I am convinced this can be done with the cooperation of all sections of this august House. That will be the direction in which we will be moving.

I recognise that fiscal system is under strain. The fiscal deficit has increased but I do believe that in the short run,

even then we have manoeuvrability to spend more resource on our flagship programmes. I sincerely believe that hon. Finance Minister when he presents his Budget will unfold the Government's strategy in this regard.[R13]

But as I said, we cannot spend our way into prosperity. In the present situation there is considerable scope to increase public expenditure, particularly on infrastructure projects and that would not lead to inflation, that would only add to our development growth potential and I reckon that is the right way to deal with international slow down that has affected many countries in the world.

The world economy is inter-linked with the management of a vast country like India. There are international factors which affect us. There are also developments in security matters which also can derail the development process. If terrorism is uncontrolled, if Left Wing extremism continues to flourish in important parts of our country which have tremendous natural resources of minerals and other precious things, that will certainly affect the climate for investment. Therefore, as a Government we are committed to doing all that is in power to ensure that terrorist elements are brought under control. That is why the hon. President talked about `Zero Tolerance' for terrorism. In the same way, in dealing with Left Wing extremism we have to convince our misguided youth that violence of the gun is no way of solving any problems and that our democratic polity gives them the scope through the ballot to express their concerns and we have seen in the past that rebels of yesterdays have ended up as being rulers. That is the beauty of our Republic; beauty of our democratic polity. So, we have to operate on two fronts in dealing with these extremist elements. We cannot allow violence to be used as an instrument of getting their results. At the same time we recognise that there is a climate in which violence flourishes and it should be our objective to ensure that people are not carried away by economic and social discontent to join the ranks of the affected people. That is why walking on two legs and a firm resolve to see that law and order is maintained and simultaneously a firm commitment to ensure that the gains of development do reach to the disadvantaged sections of our society, particularly those living in the tribal areas is required.

I am conscious of the fact that the tribal population in our country has not got a fair deal. The way we administer the tribal areas; the way we send officers who are disinterested to work in these difficult tribal areas, the flow of resources is not properly monitored and there is no proper guidance in the spending of resources. I think, the whole development strategy for tribal areas in Central India at least requires a fresh look. [R14]

I promise that our Government will do all that is possible to bring the tribal communities of our country into the national mainstream. We have taken some steps in the last five years. The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, which confers rights on forest dwellers, is a step in that direction. But I do recognise much more needs to be done on the economic and social fronts to contain the discontentment in the tribal areas which often leads to naxalism or left-wing extremism.

In his speech, the hon. Leader of the Opposition, Shri L.K. Advani, mentioned that the Centre has been blamed for certain lapses by the Commission of Inquiry set up by the Maharashtra Government in connection with the terrorist attack in Mumbai on November 26. As Members of Parliament are aware, the Government of Maharashtra had set up a Two-member Commission of Inquiry to inquire into the events of that day and the manner in which the State Government had responded to the attack. I understand that the Commission of Inquiry has submitted its Report to the State Government. The State Government would, no doubt, be tabling the Report in the Maharashtra Legislature, together possibly with an Action Taken Report. It is not possible, therefore, to comment at this stage on the contents of the Report of the Commission of Inquiry before the Report is formally tabled on the floor of the State Legislature. I shall, therefore, refrain from commenting on the inferences drawn by the hon. Leader of the Opposition about a Report that is yet to be placed on the floor of the State Assembly.

I would, however, like to inform the House about the several steps that have been taken since November 2008 to further tighten the vigil against future terrorist attacks of this nature. As Members are aware, the perpetrators of the November 26 attack came by sea. We were all aware of our vulnerability to such attacks from this quarter and had already taken a number of steps, but obviously these were inadequate. A massive effort has hence been taken to streamline our maritime security which included the setting up of a Maritime Command under the Coast Guard with overall responsibility vested with our Navy.

We have increased the number of Marine Police Stations to supplement the efforts of the Coast Guard and the Navy. There have been several other steps that have been taken. But I shall enumerate only a few. Improvements in intelligence sharing is one. The Multi Agency Centre has been fully energised and Subsidiary Multi Agency Centres constituted in more States. The process will be completed shortly. The Net-Centric Information Command structure is being put in place to achieve online transfer of all actionable intelligence in a streamlined manner. Generation of actionable intelligence has simultaneously been given priority and measures put in place for this purpose. Technical innovation and technical support to

intelligence production has been given the highest priority. Steps have also been taken to improve the quality of intelligence analysis. Investigation into serious terrorist offences will, from now on, be the responsibility of the newly-constituted National Investigation Agency.[115]

Additional legal measures taken include - apart from the new NIA Act - significant amendments to the Unlawful Activities (Prevention) Act. The Home Minister is in constant dialogue with Chief Ministers of States keeping them informed of the specific aspects of the two new pieces of legislation.

Madam, following the terrorist attacks in Mumbai on 26th November, 2008, the imperative necessity to have dedicated counter terrorist forces has been further reinforced. The National Security Guard is the principal counter terrorist force in the country. A major effort has been made to improve its capability, improving better mobility and state-of-the-art equipment. At least, four new NSG hubs have been set up in different parts of the country. In addition, certain other dedicated counter terrorist forces are sought to be created.

Madam, it goes without saying that both the challenges of the troubled times that we live in terms of security of our nation and the unique opportunities within our reach for the well being of our people, enjoin us to work together for common goals. I am grateful to the hon. leaders of the Opposition who offered their support on both these counts. I consider it the duty of my Government to build further unity of purpose. I have always felt that our differences will melt away when we consider the overwhelming nature of the challenge that our country faces.

Madam, I would like to say a few words about our relations with our neighbours. We are living in a neighbourhood of great turbulence. I have believed India cannot realize its ambitions unless there is peace and prosperity in South Asia as a whole and if our neighbourhood is suffering from instability, turbulence that has direct bearing on our own evolution as a democratic polity committed to sustained growth and development. I have, therefore, a vision for a transformed South Asia where, with the cooperation of all our neighbours, we move from poverty to prosperity, from ignorance to knowledge society and from insecurity to lasting peace. What is at stake is the future of one-and-a-half billion people living in South Asia. I sincerely believe it is in our vital interest therefore to try again to make peace with Pakistan. I recognise, it takes two hands to clap. There are some disturbing trends, but I do hope that the Government of Pakistan will create an atmosphere in which we can realize this vision. I expect the Government of Pakistan to take strong, effective and sustained action to prevent the use of their territory for the commission of acts of terrorism in India, or against Indian interests, and use every means at their disposal to bring to justice those who have committed these crimes in the past, including the attack on Mumbai. I believe that such actions will be welcomed by the peoples of both countries.[t16][t17]

If the leaders of Pakistan have the courage, the determination and statesmanship to take this road to peace, I wish to assure them that we will meet them more than half way.

I should say a few words about Sri Lanka. We have centuries-old ties with the people of Sri Lanka and we have a deep and abiding interest in the well-being of the Tamil people in that country. The Tamil problem is larger than the LTTE and I sincerely hope that the Sri Lankan Government will show imagination and courage in meeting the legitimate concerns and aspirations of the Tamil people to live their lives as equal citizens and with dignity and self-respect. We have been taking an active part in the relief and rehabilitation of the Internally Displaced Persons in Sri Lanka and I have already earmarked Rs.500 crore for this purpose. We are willing to do more to restore normalcy and to return such people to their rightful homes and occupations.

In this House as well as in the other House, Members have expressed concerns about the developments in Australia. Madam, Australia has emerged as a major destination for Indian students. Like many other Members who have spoken in this House, I have been appalled by the senseless violence and crime, some of it racially motivated against our students in Australia. I propose to engage the authorities in Australia in a high level dialogue with a view to taking stock of the situation and to providing adequate security for Indian students.

Madam, I have already spoken to Prime Minister Rudd of Australia on this subject. He assured me that any racist attacks on Indian students would be strongly dealt with. He made a Statement in Parliament in which he condemned and deplored the attacks and said that they were unacceptable. He emphasised that Australia is a multi-cultural nation which respects and embraces diversity. He said that these would be countered with the full force of the law.

Madam, I do not wish to under-play the anxiety of the parents of our students, but I wish to request the media to be mindful of the fact that there are over 200,000 Australian citizens of Indian origin. We should be mindful of their interests and avoid willy-nilly creating a situation where these citizens of Australia of Indian origin become the targets of racist intolerance. India and Australia have very good relations and it has been our effort to widen and deepen these ties in the

last five years.

Madam, I should say a few words about our relations with China. Hon. Members have raised the issue of our relations with China and I should say that China is our strategic partner. We have a multi-faceted relationship with China. There is enough space – I have said so often – for both China and India to develop and contribute to global peace, stability and prosperity. We do not see our relations with China in antagonistic terms. We have a large trading relationship, we consult each other on global issues, whether in the G-20 process on climate change or terrorism, and we share a common commitment to maintain peace and tranquillity on our border.

There are, of course, issues which are complex such as the boundary question. But we have agreed upon a mechanism to address this matter. We wish to build a strong and stable relationship with China. This is in the mutual interest of both our countries. I have been assured by the Chinese leadership – I have interacted with them extensively in the last five years – that they also subscribe to the views I have expressed just now. But whether it is China or any country, we will ensure the territorial integrity and unity of our country and protect the security in every manner necessary. The House should have no misgiving on that score.

Madam, the President's Address has covered a vast territory. I could not do justice to all the points that have been raised. But as I listened to the debate, I was struck by an underlying sense of unity on all sides that India should move forward as a united nation to achieve its coveted place in the comity of nations. That is the mandate, a mandate for change, a mandate for inclusive development, a mandate to strengthen the secular foundations of our magnificent republic. It is to these tasks that I commit our Government and I invite all hon. Members to join me in passing this Motion of Thanks unanimously.

MADAM SPEAKER: A number of amendments have been moved by Members to the Motion of Thanks. Shall I put all the amendments to the vote of the House together or does any hon. Member want any particular amendment to be put separately?

I shall now put all the amendments together to the vote of the House.

All the amendments were put and negatived.

I shall now put the Motion to the vote of the House.

The question is:

"That an Address be presented to the President in the following terms:-

'That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which she has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on June 4, 2009'."

The motion was adopted.